कौन सी शक्तियां समुत्थान का वाहक बन सकती हैं? *

शक्तिकांत दास

कारोबार के क्षेत्र में भारत के बड़े अधिनायकों और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ संवाद के इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम निडर होकर इस महामारी के दौरान रखा जिसका स्वरूप अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, जो प्रतिदिन हमारी दृढ़ता की तथा जीवन, घर, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को बचाने की हमारी क्षमता का परीक्षा लेती है।

अगस्त के अंत में आई नेशनल स्टेस्टिक्स ऑफिस (एनएसओ) की प्रेस विज्ञप्ति कोविड-19 के विनाश की एक बेबाक तसवीर थी। फिर भी, कृषि गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक, विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) और बेरोजगारी के लिए निजी अनुमान ति2 (दूसरी तिमाही) में आर्थिक गतिविधि के कुछ स्थैर्य का संकेत दे रहे हैं, जबकि कई क्षेत्रों में संकुचन भी कम हो रहे हैं। हालांकि, समुत्थान के पाँव अभी पूरी तरह जमे नहीं हैं और इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में आए उठान, जून और जुलाई में सपाट होते प्रतीत हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के प्रयासों को जिस तरह बढ़ते संक्रमणों का सामना करना पड़ रहा है सारे संकेत ये हैं कि, समुत्थान की संभावना क्रमिक है।

आकलन है कि जीवित स्मृति में वैश्विक अर्थव्यवस्था का मौसमी रूप से समायोजित तिमाही-दर-तिमाही आधार पर सबसे तेज़ संकुचन अप्रैल-जून 2020 में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर के अनुसार, आकलन है कि 2020 के ति2 (दूसरी तिमाही) में विश्व व्यापार में वर्ष-दर-वर्ष 18 प्रतिशत से अधिक की तीव्र गिरावट दर्ज हुई है। उच्च आवृत्ति संकेतक अप्रैल-जून तिमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में एक ढलान की ओर इशारा करते हैं और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरो-क्षेत्र और रूस जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं में समुत्थान है। अगस्त में वैश्विक विनिर्माण व सेवा पीएमआई क्रमश: 51.8 और 51.9 रहे जबकि जुलाई में दोनों 50.6 पर थे। तथापि संक्रमण अमेरिकी राज्यों में कम होने का नाम नहीं ले रहा तथा कई यूरोपीय व एशियाई देशों में फिर से बढ़ रहा है जिसके चलते कुछ देशों को नए सिरे से रोकथाम के कदम उठाने पड़ रहे हैं।

बड़े नीतिगत प्रोत्साहन (पॉलिसी स्टीमुलस) और हिचकिचाते आर्थिक समुत्थान के संकेतों के बाद वैश्विक वित्तीय बाजार सकारात्मक हुए हैं। फरवरी-मार्च में 'कोविड-क्रैश' के बाद विकसित व उभरती दोनों प्रकार की बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों ने वापसी की है। जोखिम की भूख में सुधार के बादविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफलों में वृद्धि हुई है जिससे निवेशकों का रुझान अधिक जोख़िम वाली आस्तियों की ओर मुड़ा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) में संविभागों का प्रवाह फिर से शुरू हुआ है और इस कारण से तथा औसत मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखने को लेकर फेड के हाल के संवादों के बाद यूएस डॉलर की कमजोरी के कारण भी ईएमई मुद्राएं ऊपर उठी हैं। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में सर्वकालिक ऊँचाई पर पहुँचने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर स्वर्ण कीमतों में नरमी आई।

रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर में शुरुआत में बड़ी कटौती और पूरी प्रणाली के साथ विशेष लक्ष्यों के लिए चलनिधि डाले जाने के कारण भारत में सभी क्षेत्रों में वित्तीय बाजार स्थितियां काफी सुलभ हुई हैं। सरकार के उधार कार्यक्रम में अच्छी वृद्धि के बावजूद, चलनिधि में लगातार बड़े अधिशेष की स्थिति के चलते विगत एक दशक में उधारी की न्यूनतम लागत पर बिना किसी बड़े उथल-पुथल के संसाधन जुटाए जा सके हैं। अगस्त 2020 में, मुद्रास्फीति और सरकारी पत्रों की आपूर्ति में वृद्धि पर चिंताओं के बीच 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क पर प्रतिफल 35 आधार अंक बढ़ा। रिजर्व बैंक द्वारा विशेष खुले बाजार संचालन (ओएमओ) की घोषणा और जी-सेक बाजार के सुव्यवस्थित कामकाज की बहाली के लिए उठाए गए अन्य कदमों के बाद, बॉन्ड प्रतिफल नरम पड़े हैं और सितंबर में एक संकीर्ण दायरे में

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 16 सितंबर, 2020 को फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में संबोधन

ट्रेड हुए हैं। यद्यपि, बैंक ऋण वृद्धि ठंडी रही है कंपनी निकायों (कॉरपोरेट बॉडिज़) के वाणिज्यिक पत्र, बॉन्डों, डिबेंचरों और शेयरों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश इस वर्ष अब तक (28 अगस्त तक) ₹5,615 करोड़ बढ़ा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 24 32,245 करोड़ की गिरावट आई थी। इसके अलावा, वित्तपोषण की स्थितियों में नरमी और स्प्रेड की अधिक संकीर्णता के कारण 2020-21 में अगस्त तक लगभग ₹3.2 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्डों का रिकॉर्ड निर्गम हुआ।

कोविड के बारे में तत्काल नीतिगत कदम अर्थव्यवस्था की स्थिरता को प्राथमिकता और शीघ्र समुत्थान को सहयोग देना था। फिर भी, संकट के बाद मध्यावधि में ठोस और संवहनीय उच्च विकास की नीतियां, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, और आज के अपने संबोधन में मैं सीधे उस मुद्दे पर केंद्रित होना चाहता हूँ – समुत्थान शुरू होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य दीर्घावधि औसत वृद्धि पथ पर ला सकने की संभावना किसमें है।

27 जुलाई 2020 को भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के साथ अपने संवाद में मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे पाँच प्रमुख गतिमान परिवर्तनों की बात की थी: (i) भाग्य चक्र का कृषि क्षेत्र की तरफ़ मुड़ना; (ii) नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मुड़ता ऊर्जा उत्पादन का स्वरूप; (iii) संवृद्धि को गति देने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा स्टार्ट-अप्स का उपयोग; (iv) आपूर्ति/मूल्य शृंखला में बदलाव, घरलू और वैश्विक दोनों; (v) संवृद्धि की गति बढ़ाने वाली बुनियादी संरचना।

आज, मैं उन पाँच क्षेत्रों को लेना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है, मध्यावधि में भारत की वृद्धि को बढ़ाने और बनाए रखने की हमारी क्षमता का निर्धारण करेंगे: (i) मानव पूँजी, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य में; (ii) उत्पादकता; (iii) निर्यात, जो वैश्विक मूल्य शृंखला में भारत की भूमिका को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है; (iv) पर्यटन; और (v) खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उत्पादकता लाभ।

(i) मानव पूँजी: शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्त्व

लोगों में निवेश किसी देश में उपलब्ध कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है, और यह भावी विकास संभावना के भरपूर दोहन के लिए महत्वपूर्ण है। प्लेटो, अरस्तू, सुकरात और कौटिल्य के समय से ही शिक्षा का महत्व स्थापित है। हाल के दशकों में आर्थिक विकास हेतु इसके महत्व पर उत्तरोत्तर ध्यान गया है, विशेष रूप से टी डब्ल्यू शुल्त्स, गैरी बेकर, रॉबर्ट लुकास और जेम्स हेकमैन समेत कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्य में। अंतर्जात संवृद्धि सिद्धांत में मानव पूँजी के रूप में शिक्षा को एक स्पष्ट मान्यता मिली है जो देश भर के अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

भारत में, उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक, शिशु मृत्यु दर कम, स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति और गरीबी भी कम देखी गई है। तथापि, हमारे समग्र श्रम उत्पादकता वृद्धि में, शिक्षा और कौशल विकास आधे प्रतिशत से कम का योगदान देते हैं। जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए, हमें शिक्षा और कौशल प्राप्ति पर व्यय में बड़ी वृद्धि करनी होगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में निवेश का फायदा औसत मजदूरी में वृद्धि के रूप में मिलता है। अपनी ग्लोबल एड्यूकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2012 में, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने यह बात रेखांकित की है कि शिक्षा पर खर्च किया गया प्रत्येक यूएस $1 लगभग यूएस $10 से यूएस $ 15 तक की अतिरिक्त आय उत्पन्न करता है। विश्व बैंक (2014) के एक अध्ययन से पता चला कि स्कूली शिक्षा का एक अतिरिक्त वर्ष आय में एक वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि करता है। पर्यावरण / जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा उपयोग, नागरिक भागीदारी और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति अधिक संवेदनशीलता के माध्यम से भी उच्च शिक्षा आर्थिक विकास में योगदान देती है।

एक ऐतिहासिक और नए युग के अत्यंत आवश्यक सुधार, नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी), में मानव पूँजी को प्राथमिकता दी गई है जिससे भारत के अनुकूल जनसांख्यिकी का लाभ मिलने की संभावना बनती है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य के लिए पुरजोर कोशिश होनी चाहिए। सार्वजनिक निजी सहभागिताएं (पीपीपीज़) आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विकास कर सकती हैं जिससे निजी निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता पर आँच नहीं आएगी और किफ़ायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। एनईपी से नए वित्तपोषण के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों पर भारतीय बैंकों

और वित्तीय प्रणाली को अग्रसक्रिय प्रतिसाद देने की आवश्यकता होगी।

शिक्षा की उपलब्धता में सुधार के अलावा, शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा जिससे आर्थिक विकास पर शिक्षा के परिणाम को आकार दिया जा सके। स्कूली शिक्षा में बिताए महज कुछ औसत वर्षों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है कौशल प्राप्त करना। शिक्षा की गुणवत्ता पहलू के मूल्यांकन के लिए अक्सर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है: पठन और भाषाई प्रवीणता; गणित और संख्याओं में निपुणता; और वैज्ञानिक ज्ञान और समझ[1]. । शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर प्लस 2 स्तर तक के स्कूलों में बुनियादी स्तर पर शुरू होना बहुत जरूरी है। एक अन्य स्तर पर, एनईपी में घोषित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन समकक्ष-समीक्षित अनुसंधान के वित्तपोषण तथा विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शोध को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के एक मंच के रूप में एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम का निर्माण तेजी से बदलते श्रम बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

मानव पूंजी का एक और महत्वपूर्ण घटक है स्वास्थ्य । अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा और उत्पादक रूप से सक्रिय वर्षों को बढ़ाता है। उच्च आय वाले देशों में, 2017 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय लगभग यूएस $2937 था, जबकि निम्न मध्यम आय वाले देशों में (जिसमें भारत भी शामिल है) यूएस $130 । प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम (पीएमएनडीपी), नि: शुल्क दवा और नैदानिक सेवा व्यवस्था जैसे प्रयासों से स्वास्थ्य सेवा के अधिक बेहतर तथा किफायती होने की उम्मीद है । किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ है, जिसके द्वारा 21 वीं सदी के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की नींव रखी गई है । इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अस्पतालों को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना में अन्तर-राज्य और अन्त:राज्य स्तर पर बड़े पार्थक्य को देखें तो कोविड ने मृत्यु दर को नियंत्रित करने में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता के महत्त्व को उजागर किया है। आपातकाल में स्वास्थ्य के संकट से निपटने में स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में वृद्धि के लिए किया गया कार्य जहाँ प्रशंसनीय है, वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एनईपी की तरह एक अधिक व्यापक पद्धति की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें, भारत में जेब से किए गए खर्च के बड़े बोझ को देखते हुए, बीमा के गहरे पैठ और निवारक देखभाल को भी कवर करना होगा । नए मेडिकल कॉलेजों, पीजी सीटों की अधिक संख्या तथा पैरामेडिक्सऔर नर्सिंग हेतु कॉलेजों के निर्माण द्वारा स्वास्थ्य परितंत्र में सुधार पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ii) उत्पादकता वृद्धि

किसी भी दृष्टिकोण से दुनिया भर के देशों के उत्पादकता स्तरों पर कोविड-19 के घाव लंबे समय तक चलेंगे। विश्व बैंक के एक हालिया आकलन[2] के अनुसार, श्रम के विस्थापन, मूल्य शृंखलाओं के विघटन और नवाचारों में कमी के कारण कोविड-19 उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अनुमान है कि अतीत में महामारियों की पिछली घटनाओं के दौरान - गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (सार्स), मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (मर्स), इबोला और जीका - उत्पादकता में तीन वर्षों में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई। उत्पादकता पर कोविड प्रभाव बहुत बड़ा होने की उम्मीद की जा सकती है।

रिज़र्व बैंक द्वारा होस्ट किए गए एक डेटाबेस केएलईएमएस (पूंजी; श्रम; ऊर्जा; सामग्री; और सेवाएँ), से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 1980-81 से 2017-18 की अवधि में कुल मिलाकर औसतन 0.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की उत्पादकता वृद्धि देखी। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के तत्काल बाद की अवधि - 2008-09 से 2012-13 तक – में सालाना उत्पादकता में 0.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि उसके बाद की अवधि में 2017-18 तक वार्षिक उत्पादकता में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । 1980-81 से 2017-18 की अवधि में भारतीय

[1] वर्ल्डइंडियाडेटा.ऑर्ग

[2] विश्व बैंक, 2020 "ग्लोबल प्रॉडक्टिविटी: ट्रेंड्स, ड्राइवर्स एंड पॉलिसीज़ (चैप्टर 3: ह्वाट हैपेन्स टू प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग मेजर एडवर्स इवेंट्स)।

अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी वृद्धि में उत्पादकता वृद्धि का योगदान लगभग 15 प्रतिशत था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, इसका योगदान उल्लेखनीय रूप से लगभग 34 प्रतिशत तक बढ़ गया।

विश्व भर में दिए गए कुल पेटेंट में आवेदित व भारत को दिए गए और दिए गए पेटेंट का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ रहा है। हालाँकि, भारत का हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम पर बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय में निजी क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि भारत में, अनुसंधान और विकास व्यय का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा खर्च किया जाता है, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, पृथ्वी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी पर। अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए कदम बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, जिसमें सरकार सक्षमकारी परिवेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

वित्तीय सेवाओं में नवाचारों को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नई क्षमताओं पर केंद्रित एक इनोवेशन हब की घोषणा की है जो वित्तीय समावेश और कुशल बैंकिंग सेवाओं की गहराई में सहायक हो सकता है। पहले से चल रहे प्रयासों के परिणाम आ रहे हैं। भारत ने हाल ही में पहली बार 2020 के वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) की सूची में शीर्ष 50 देशों के समूह में प्रवेश किया है। पिछले साल नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स) को देश के सभी राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की दिशा में व्यापक तौर एक बड़े कदम के रूप में देखा गया है। इस प्रक्रिया को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा विशेषत: भारत में बचत और निवेश की दर में ट्रेंड गिरावट को देखते हुए।

(iii) निर्यात और वैश्विक मूल्य शृंखलाएं (जीवीसी)

जीएफसी के बाद की अवधि में, एक विचार सामने आया है कि निर्यात-चालित वृद्धि का युग समाप्त हो गया है, और सही समय पर निर्यात को प्राथमिकता नहीं देने के कारण भारत अवसर से चूक गया। जीएफसी के बाद दुनिया भर में, निर्यात के रास्ते की प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं: (ए) व्यापार भागीदारों द्वारा संरक्षणवाद में व्यापक वृद्धि; (बी) कमजोर वैश्विक मांग की स्थितियां; (ग) नीचे की ओर दौड़ (प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यह्रास, सब्सिडी, कर और नियामक रियायतों के नीतिगत मिश्रण का उपयोग करके अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाना); और (डी) स्वचालन (ऑटोमेशन), जिससे सस्ते श्रम से मिलने वाले लागत के फायदों में कमी आती है।

इन बाधाओं, और जीएफसी के बाद की अवधि में विश्व जीडीपी वृद्धि के व्यापार घटक में महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद भी, बड़े पैमाने पर व्यापार के परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य से निर्यात के विस्तार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जहां विश्व व्यापार का दो तिहाई से अधिक हिस्सा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के जरिये होता है (जीवीसीज़)[3]। किसी देश की जीवीसी भागीदारी जितनी अधिक होगी, व्यापार से उसे उतने ही अधिक लाभ होंगे क्योंकि इसमें जुड़ने वाले देशों को जीवीसी में शामिल अन्य देशों के तुलनात्मक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। परिवहन, बैंकिंग, बीमा, आईटी और कानूनी सेवाएं, ब्राण्डिंग, मार्केटिंग और विक्रयोत्तर सेवाएं (आफ्टर सेल सर्विसेज़) जैसी सेवाएं जीवीसी का अभिन्न अंग हैं।

कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जीवीसी में भारत की भागीदारी कम रही है। भारत की वैश्विक उपस्थिति रत्न व आभूषण, चावल, मांस और झिंगा (श्रिम्प्स), वस्त्र, कपास, तथा दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कम जीवीसी वाले उत्पादों में है।

उदीयमान क्षेत्रों में कोविड के बाद की अवधि में दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स में उच्च निर्यात की संभावना है जहाँ भारत के पास कुछ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। भारत जेनेरिक दवाओं और टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है जिसके पास कम लागत पर दवा निर्माण की मजबूत विशेषज्ञता है। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर वितरण हेतु बड़े पैमाने पर टीके का उत्पादन करने के लिए कुछ भारतीय निर्माताओं ने वैश्विक फार्मा कंपनियों के साथ पहले ही नई साझेदारी कर ली है। सरकार ने थोक दवा (बल्क ड्रग) पार्कों को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश पैकेज को भी मंजूरी दी है और दवा मध्यवर्तियों और सक्रिय दवा सामग्री (एक्टिव फॅर्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट्स) के घरेलू उत्पादन को

[3] डॉलर, डेविड (2019), "ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट रिपोर्ट", विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा।

बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-बद्ध प्रोत्साहन योजना मौजूद है। आईटी हार्डवेयर के उपकरण, बिजली के सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार और ऑटोमोबाइल सहित अन्य जीवीसी आधारित "नेटवर्क उत्पादों" पर एक स्पष्ट रूप से केंद्रित नीति भी भारत की निर्यात रणनीति को धार देगी जिसमें उच्चतर मूल्य परिवर्धन के लिए काफी गुंजाइश होगी।

घरेलू नीतियों को जीवीसी में भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य के साथ निर्यात में स्थानीय और विदेशी सामग्री के सही मिश्रण पर ध्यान देना होगा। आयात और निर्यात दोनों से जुड़ी फर्मों को गैर-व्यापारिक (नॉन-ट्रेडिंग) फर्मों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक पाया गया है (विश्व बैंक, 2020)[4]। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से व्यापार भागीदारों का चयन करते समय, वैश्विक अनुभवों से सीखना और उन व्यापार समझौतों का पोषण भी महत्त्वपूर्ण है जो पारंपरिक बाजार पहुँच के मुद्दों से आगे जाते हैं। निवेश, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का जीवीसी व्यापार पर एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव है और भारत के निर्यात परितंत्र में इनको बड़े ध्यान से विकसित और समाहित करने की आवश्यकता है।

(iv) विकास के इंजन के रूप में पर्यटन

पर्यटन अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में से एक रहा है जो कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। साथ ही, यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां स्थिति सामान्य होने पर दबी हुई मांग (पेंट अप डिमांड) से वी (v) के आकार की रिकवरी आ सकती है।

भारत में विभिन्न प्रकार की पर्यटक रुचियों - धर्म; साहसिक(एडवेंचर); चिकित्सा उपचार; स्वास्थ्य और योग; खेल; फिल्म निर्माण; और पर्यावरण पर्यटन – को पूरा करने लायक विशाल संभावनाएं हैं। हमारे पास चार प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट, 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल[5], 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 7,000 किमी से अधिक का समुद्र तट, वृष्टि वन, रेगिस्तान, आदिवासी प्राकृतिक वास और एक बहु-सांस्कृतिक आबादी है। फिर भी चुनौती अपने पर्यटन बाजार को ऊँचा उठाने और आर्थिक विकास में इसके योगदान के वृद्धि की है।

थर्ड रिपोर्ट ऑफ़ टूरिज़्म सैटेलाइट अकाउंट फ़ॉर इंडिया (टीएसएआई) 2018 के अनुसार, 2016-17 में जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 5.1 प्रतिशत था और रोजगार में 12.2 प्रतिशत (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रमश: 5.32 प्रतिशत और 6.88 प्रतिशत हिस्से के साथ)। 2018-19 में, रोजगार में पर्यटन की हिस्सेदारी बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई, जिसका कुल आकार 87.5 मिलियन था। इस प्रकार, इस क्षेत्र में रोजगार लोच अधिक प्रतीत होता है। भारत ने 2019 में 10.89 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में इस क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विदेशी मुद्रा आय ₹2 ट्रिलियन थी, जो वर्ष-दर-वर्ष स्तर पर 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम (डबल्यूईएफ़) के ट्रेवल एंड टूरिज़्म कम्पीटीटिवनेस इंडेक्स 2019 में छह स्थान की छलांग लगाते हुए 140 काउंटियों में यह देश 34 पर पहुँचा।

क्षेत्र की संभावना को देखते हुए, सरकार ने योजनाबद्ध नीति समर्थन दिया है। ऐतिहासिक स्थलों और विरासत शहरों सहित देश में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय की दो प्रमुख योजनाएँ हैं: थीम-आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन; और प्रशाद के नाम से एक तीर्थस्थान कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत विस्तार अभियान।

अपनी क्षमता के अनुरूप यदि पर्यटन को अर्थव्यवस्था में और अधिक योगदान देना है तो सहयोग हेतु क्षेत्र में नीतिगत स्तर पर बहुस्तरीय हस्तक्षेपों की समीक्षा और सुधार करना पड़ सकता है। यात्रा व पर्यटन में फ्रांस और स्पेन जैसे विश्व के कुछ अग्रणी देशों पर गौर करें तो पता चलता है कि इनके पास न केवल उत्कृष्ट प्राकृतिक व सांस्कृतिक संपदाएं हैं, बल्कि एक असाधारण आकर्षक पर्यटन बुनियादी ढाँचे को सपोर्ट करने वाली नीतियां भी हैं जिसमें सभी रेंज के विकल्पों वाला एक उच्च होटल घनत्व, विपुल मार्ग क्षमता वाली बढ़िया सार्वजनिक परिवहन प्रणाली व हवाई संपर्कों का नेटवर्क शामिल है जिसकी मार्ग क्षमता (रूट कैपेसिटी) काफ़ी अधिक है और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षा और सुरक्षा बेहतर है।

सिंगल प्वाइंट बुकिंग, सेवा प्रदाताओं (ट्रेवल एजेंटों, परिवहन ऑपरेटरों, होटलों, पर्यटन गाइडों, आदि) के ई-पंजीकरण की व्यवस्था के साथ परिवहन के विभिन्न माध्यमों (हवाई/ट्रेन/मेट्रो/सड़क/समुद्र से जोड़ने वाली) को बेहतर बनाने और एकीकृत

[4] विश्व बैंक (2020), वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वाशिंगटन, डी.सी.

[5] 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित।

करने की दिशा में पहल की आवश्यकता है। अनुपालन न करने पर दंड के सख्त प्रावधान और साथ ही घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रभावी और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली से पर्यटकों का विश्वास बढ़ेगा। एक निजी एजेंसी[6] द्वारा किए गए शोध के अनुसार अगर हम अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन को 20 मिलियन तक बढ़ा पाएं (यानी, वर्तमान आगमनों के लगभग दोगुना), तो वृद्धिशील आय यूएस$19.9 बिलियन होगी, जिससे यात्रा और पर्यटन उद्योग में और दस लाख (एडिशनल 1 मिलियन) लोगों को लाभ होगा। [7]

(v) अधिशेष प्रबंधन के लिए खाद्य प्रसंस्करण

कोविड ने खाद्य सुरक्षा और खाद्य वितरण या आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के महत्व को भारत में सार्वजनिक नीति पर बहस के शीर्ष में ला दिया है। खाद्यान्न और बागवानी फसलों के बरस दर बरस रिकॉर्ड उत्पादन ने भारत को खाद्य अधिशेष अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इस चुनौती को देखते हुए, हाल के वर्षों में नीतिगत स्तर पर इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान उत्पादनोत्तर अड़चनों को दूर करने पर लगा है, जिसमें कृषि-व्यवस्थाएं (लॉजिस्टिक्स), भंडारण सुविधाएं, प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और मार्केटिंग शामिल हैं। प्रसंस्कृत भोजन (प्रोसेस्ड फ़ूड) पर अधिक ध्यान एक रास्ता है जो अधिशेष प्रबंधन की बहु-आयामी चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। कृषि उत्पादन में अधिक मूल्य संवर्धन, खाद्य अपव्यय में कमी, खाद्य कीमतों में स्थिरता, निर्यात के अवसरों में वृद्धि, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर लाकर, किसानों की आय और उपभोक्ता हेतु विकल्पों को बढ़ाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास से कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लाभान्वित होने की संभावना है।

खाद्य प्रसंस्करण एक उदीयमान उद्योग है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शहरीकरण, तथा गुणवत्ता और सुरक्षा (सेफ्टी) के संबंध में उपभोक्ता धारणाओं में बदलाव द्वारा वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता की झोली में इसका महत्व समय के साथ बढ़ा है। विकास की विशाल संभावनाओं के बावजूद, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी एक नवजात अवस्था में है, जो देश में उत्पादित कुल खाद्य पदार्थों के 10 प्रतिशत से कम का योगदान दे रहा है। परिणामत:, दुनिया में कई कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में भारत का स्थान काफी नीचे है।

मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यत: घरेलू स्तर पर सिमटा है, जिसमें कुल उत्पादन का केवल 12 प्रतिशत निर्यात होता है। प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर भारत वैश्विक कृषि मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकता है जिसमें गुणवत्ता मानक एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं हैं। भारत में, समग्र सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का योगदान जहाँ केवल 1.6 प्रतिशत है, पंजीकृत और अनिगमित क्षेत्रों में इसका योगदान 1.8 मिलियन (12.4 प्रतिशत) और 5.1 मिलियन (14.2 प्रतिशत) नौकरियों का है। इसे समझते हुए, सरकार ने 2025 तक कुल कृषि उपज में प्रसंस्कृत खाद्य का हिस्सा 25 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को 2016 में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए भी खोला गया। इसके अलावा, 2017 में, भारत में बने और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स के माध्यम सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकारी मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 2015 में इसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का दर्जा दिया है।

निष्कर्ष

आज अपने संबोधन में, मैंने पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है जो कोविडोत्तर अवधि में हमारे विकास की प्रवृत्ति (ट्रेंड ग्रोथ) का आकार तय कर सकते हैं। तात्कालिक संकट प्रबंधन चुनौतियों से निपटने में, हमें प्राथमिकता में ऊपर आने वाले अपने संयुक्त लक्ष्यों - मजबूत और टिकाऊ विकास के प्रयास - के लिए रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता है। आज मैंने जिन पाँच क्षेत्रों

[6] बेन एंड कंपनी (2017), "टूरिज़्म ऑपरचुनिटी फॉर इंडिया", वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, सितंबर 2017 के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट चर्चा पत्र।

[7] "अतुल्य भारत 2.0, इंडियाज़ $ 20 बिलियन टूरिज़्म ऑपरचुनिटी", वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, 2017।

को कवर किया, उनमें से प्रत्येक में निजी कारोबार क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अवसरों को पकड़ने और 21वीं सदी की उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना को साकार करने में भारतीय कारोबारों द्वारा की गई पहल के इर्द-गिर्द ही इसके लायक समर्थकारी नीतिगत परिवेश विकसित होगा। कोविड-19 ने हमारे जीवन को बदल दिया है और यह उत्तरोत्तर स्पष्ट है कि जीवन अब कभी भी वैसा नहीं होने वाला। हमें इन मूलभूत परिवर्तनों को खतरों के बजाय मौकों के रूप में देखना चाहिए, और उन्हें खेल का पाँसा पलटने वाले प्रगति के नए अवसरों में बदलना चाहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक राष्ट्र के रूप में, हम निश्चित रूप से यह कर सकते हैं। मैं इस आशावादी संदेश के साथ समापन करना चाहूँगा।